

पूर्वोत्तर भारत में आपदा

ऋषिकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत

19 वीं और 20 वीं सदी का भारत आपदा प्रबंधन के बारे में सोच तो सकता था पर कुछ करने में असमर्थ था ।
आपदा से पहले और बाद के परिदृश्य में लोगों को उनके भाग्य पर छोड़ना एक मज़बूरी था ।

हालांकि आजादी के बाद बहुत प्रगति हासिल हुई है, लेकिन यह मुख्य रूप से आपदाके बाद राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन (Search & Rescue) तक ही सीमित था।

और यह 21 वीं सदी का भारत है जो न केवल सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर ही नहीं , बल्कि आतंकवाद और आपदा प्रबंधन जैसे वैश्विक पहलुओं पर भी दुनिया का नेतृत्व करने की आकांक्षा रखता है।

भारत इस सम्बन्ध में अपनी छमता का प्रदर्शन विश्व के आपदाओं के समय पहले भी किया है और करने के लिए तत्पर भी है। जैसे की नेपाल भूकंप, श्रीलंका, यमन क्राइसिस और अफ़ग़ानिस्तान में भारत ने अभूतपूर्व मदद किया है ।

यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि **डॉ पी के मिश्रा जी** की अध्यक्षता में एक उच्च भारतीय प्रतिनिधिमंडल (high level Indian delegates) ने जिनेवा (Geneva) में आयोजित ग्लोबल प्लेटफार्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (Global Platform for Disaster Risk Reduction) 2019 के लिए वैश्विक मंच पर भाग लिया | भारत को वित्तीय वर्ष 2020 के लिए ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी (GFDRR) के कंसल्टेटिव ग्रुप (CG) के सह-अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया ।

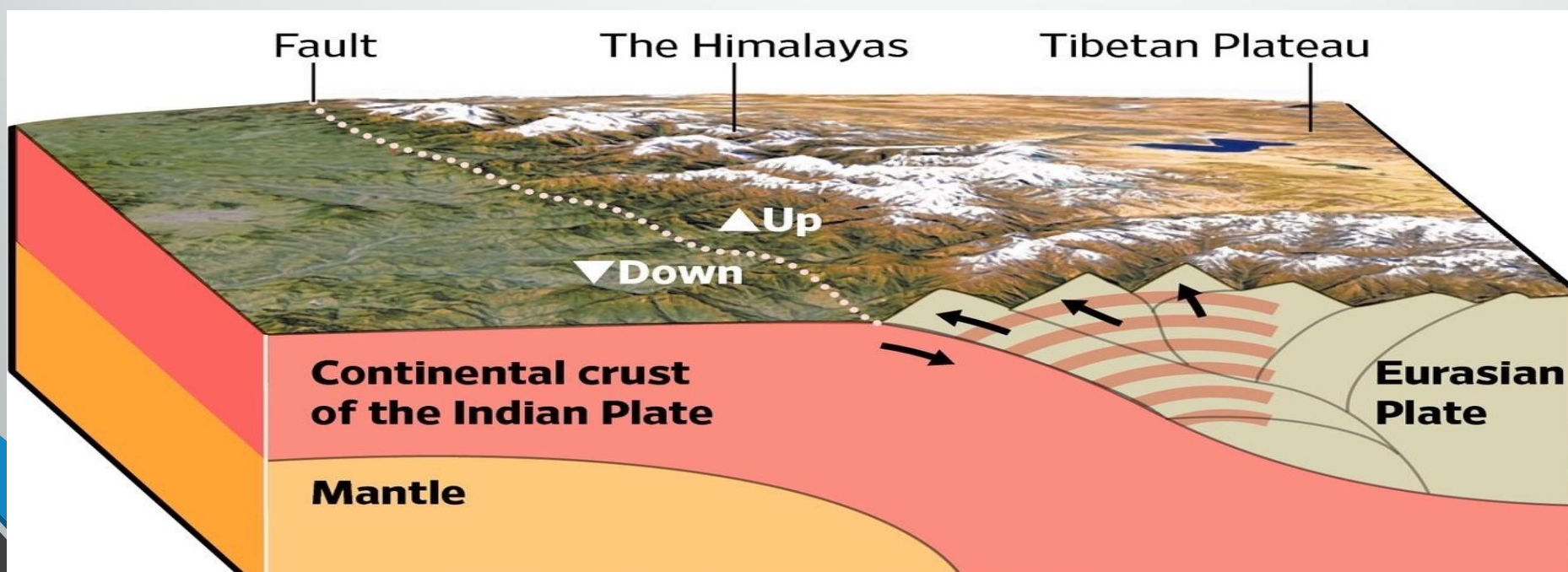
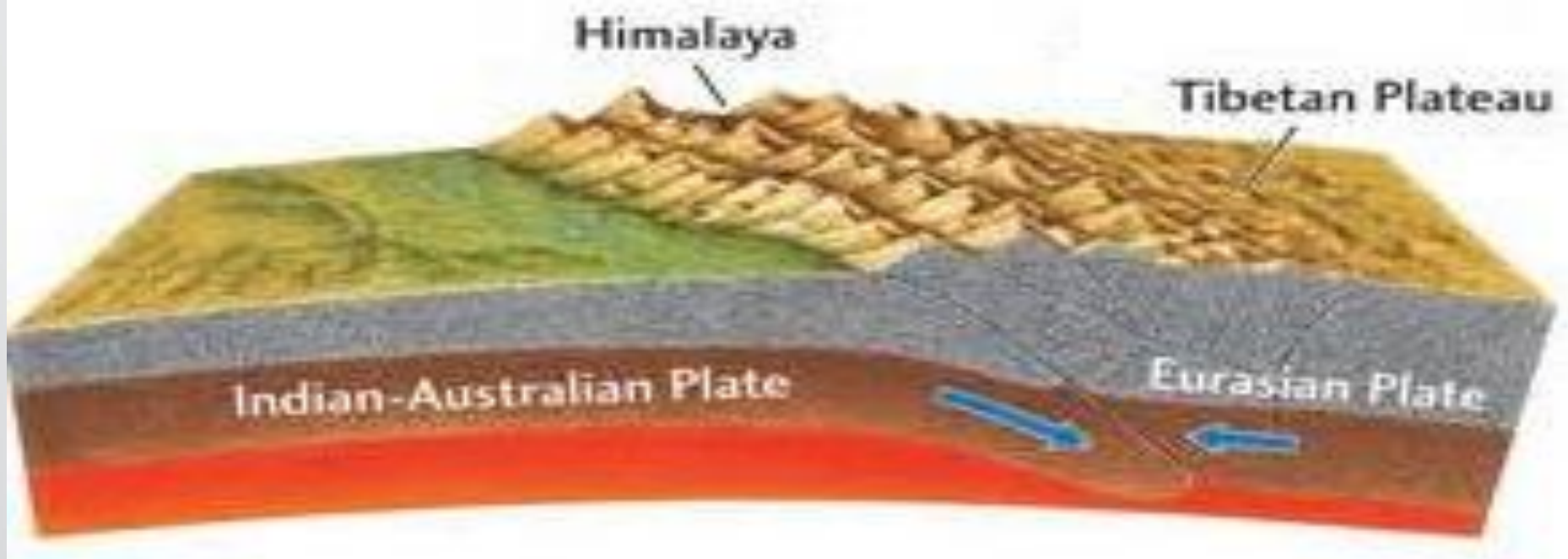
डॉ मिश्रा सेंडाइ फ्रेमवर्क (Sendai Framework) को अपनाने के बाद भारत द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी | उन्होंने कहा कि भारत न केवल बड़ी आपदाओं से मृत्यु दर को कम करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है, बल्कि लघु या मध्यम और स्थानीय रूप से विशिष्ट आपदाओं जैसे **लू (heat wave) , आंधी और बिजली (, thunderstorm and lightning)**.

चक्रवात जोखिम शमन (cyclone risk mitigation) में निवेश से बहुमूल्य मानव जीवन को बचाने में लाभ हुआ है | फेलिन (Phailinin) चक्रवात के दौरान 2013 और फानी (fani) में 2019 में हुई मौतों में काफी कमी आई है ।

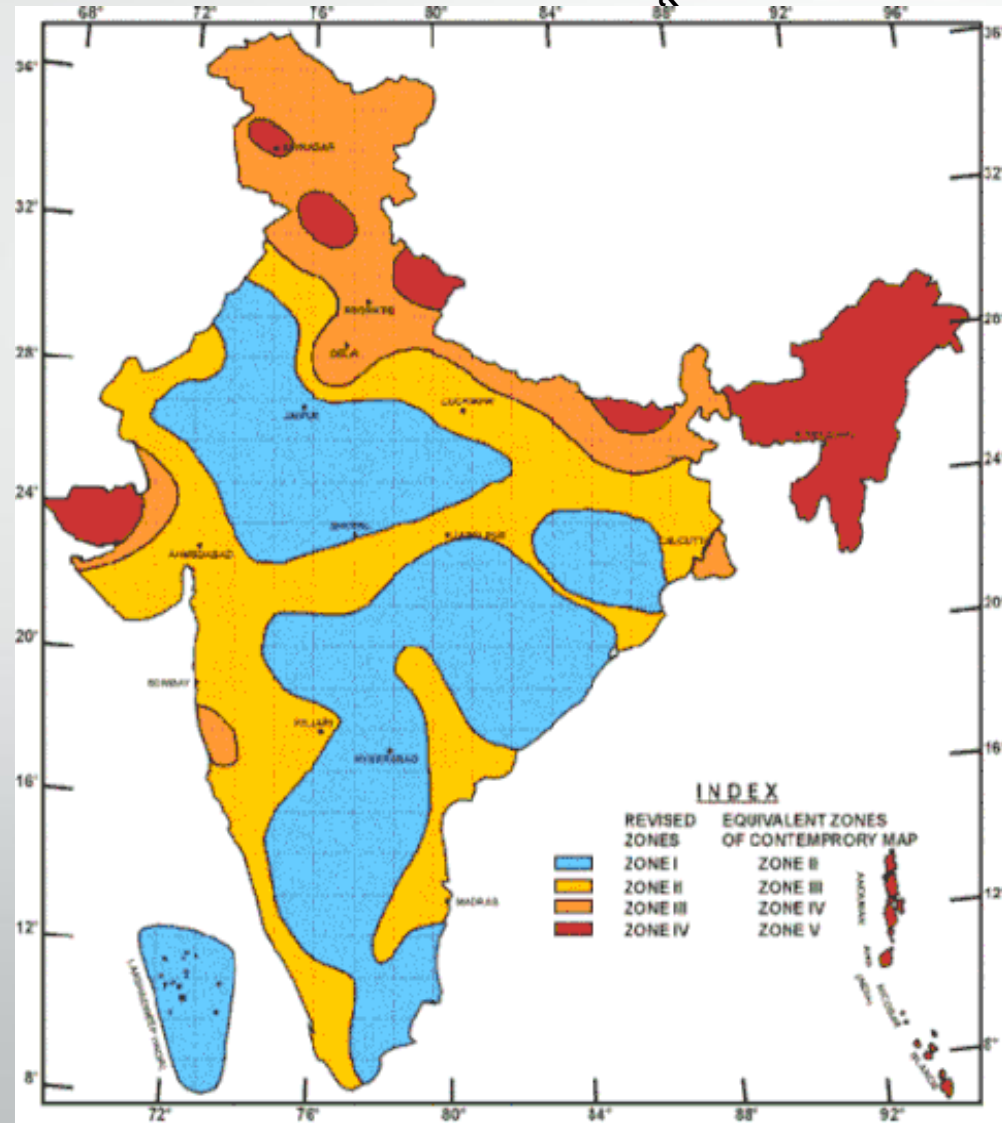
प्रकृति की सबसे अप्रत्याशित और उसकी सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक भूकंप है।

भारतीय उपमहाद्वीप में विनाशकारी भूकंपों का इतिहास रहा है।

भूकंपों की उच्च आवृत्ति और तीव्रता का प्रमुख कारण यह है कि भारतीय प्लेट लगभग **47 मिमी / वर्ष** की दर से यूरेशियन प्लेट के नीचे अग्रसर है।



भूकंपीय ज़ोनिंग मैप का नवीनतम संस्करण भारत को ४ भूकंपीय क्षेत्रों (क्षेत्र २, ३, ४ और ५) में विभाजित करता



भारत के भौगोलिक आंकड़े बताते हैं कि लगभग 54 % भूमि भूकंप की चपेट में है।

विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक भारत में लगभग 20 करोड़ शहरवासी को तूफान और भूकंप का सामना करना होगा।

वैज्ञानिक और भूकंपविज्ञानी इस बात पर एकमत हैं कि निकट भविष्य में एक बड़ा भूकंप हिमालयी क्षेत्र में आसन्न है और वे भी इसके बड़े पैमाने पर तबाही के बारे में सुनिश्चित हैं।

कहा जाता है कि यहां तक कि एक भी बड़ी आपदा समाज और अर्थव्यवस्था को दशकों तक पीछे छोड़ देती है।

नीति निर्माता और अर्थशास्त्री इस बात पर एकमत हैं कि वास्तव में आपदा के जोखिम को कम करना ही बेहतर है।

भूकंप की तैयारी भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक स्तर पर किए गए उपायों का एक समूह है।

तैयारी के उपाय भारी वस्तुओं, संरचनात्मक संशोधनों और भंडारण की बिमा से लेकर, एक आपातकालीन किट, और निकासी योजना को तैयार रखने तक हो सकते हैं।

सीस्मोलॉजिस्ट द्वारा काफी शोध प्रयासों के बावजूद, वैज्ञानिक रूप से योग्य भविष्यवाणी अभी तक किसी विशिष्ट दिन या महीने के लिए नहीं की जा सकती हैं।

भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली (ई ई डब्ल्यू एस (EEWS)) विकसित की गई है जो भूकंप की क्षेत्रीय सूचना को प्रगति से पहुंचा सकती है।

आपदा के दौरान निर्बाध जानकारी प्रदान करने के लिए दूरसंचार कंपनियां घंटों के भीतर मोबाइल टॉवर स्थापित करने में सक्षम हैं।

उपग्रह संचार और इसके द्वारा भेजे गए चित्र हमें प्लेटों की गति और आपदा अवस्थिति पर कुशलता से नज़र रखने में मदद करती हैं।

खोज और बचाव अभियान में **एन. डी. आर. एफ.** और **भारतीय सशस्त्र बलों** की बढ़ती भूमिका हमारी क्षमता को और बढ़ाती है।

आपदा प्रबंधन में हमारी तैयारियों को और आगे बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में निम्नलिखित संस्थागत उपाय भी किए गए हैं।

सरकार ने आंधी (Thunderstorm), बिजली (Lightning), फुलझड़ी (Squall), धूलभरी आंधी (Dust Storm), ओलावृष्टि (Hailstorm) और तेज हवाओं (Strong winds) से होने वाले नुकसान के जोखिम के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए हैं। कृपया ध्यान दें कि ये इस उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हत्यारा (the biggest killer) है।

२०१६ की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP, 2016) के आधार पर सभी राज्यों और भारत के 95 प्रतिशत से अधिक जिलों ने अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की हैं।

भारत डीआरआर (DDR) में अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर काम करने में विश्वास करता है।

इस उद्देश्य के लिए, भारत ने अक्टूबर 2017 में NCR में पहले BIMSTEC डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज (BIMSTEC Disaster Management Exercise) की मेजबानी की।

इसी तरह, फरवरी 2019 में, भारत ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Disaster Risk Management of the IORA) के आपदा जोखिम प्रबंधन पर एक बैठक की मेजबानी की।



“आपदा एक दर्दनाक अनुभव हो सकता है; लेकिन यह एक अच्छा शिक्षक भी हो सकता है”

सिफारिशें पेश करने से पहले महात्मा गांधी जी के कोटेशन पे बल देना चाहूंगा।

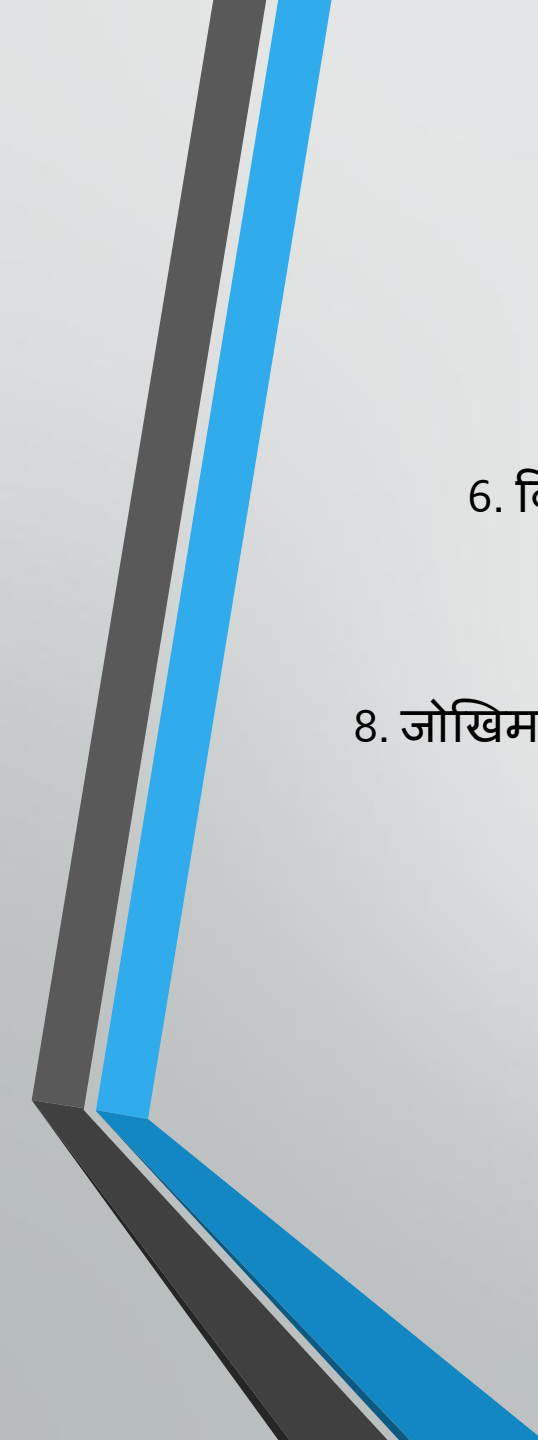
“एक तकनीकी समाज के पास दो विकल्प होते हैं। पहला, यह अनर्थकारी विफलताओं के क्रमबद्ध कमियों, विकृतियों और आत्मप्रवंचना प्रकट करने तक प्रतीक्षा कर सकती है दूसरा एक संस्कृति अनर्थकारी विफलताओं के पूर्व क्रमबद्ध विकृतियों को सुधारने के लिए सामाजिक जाँच और संतुलन प्रदान कर सकती है।”


सिफारिसों का लक्ष्य हमारी समृद्धि सामाजिक-सांस्कृतिक पद्धतियों और सामना करने के देसी कार्यतंत्र के साथ प्रोद्योगिक और ज्ञान के युग में उन्नति की सक्रियता तथा अभिमुखता स्थापित करना है।

इस सम्बन्ध में दो लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

पहला, लोगो और इमारतों को आपदाओं से बचाना, और दूसरा संकट के प्रति प्रत्युत्तर और सुधार की कारगरता को बढ़ाना।

1. संवैधानिक प्रावधान – एक नई प्रविष्टि, "आपदाओं और आपात स्थितियों का प्रबंधन, प्राकृतिक या मानव निर्मित", को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची/ concurrent list) में शामिल किया जा सकता है ।
 2. आपदा प्रबंधन पर आधारित एक नया अध्याय India@75 में जोड़ा जाना चाहिए
3. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का विश्लेषण- आपदा प्रबंधन को राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी बनी रहनी चाहिए और केन्द्र सरकार को सहायक भूमिका निभानी चाहिए ।
 - 4 . स्थानीय स्वशासन (Local Self-Governments) की भूमिका
5. आपदा से संबंधित जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन करने के लिए राहत आयुक्तों/आपदा प्रबंधन विभागों (Relief Commissioners/Disaster Management Departments) को सशक्त बनाना

- 
6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों (S&T institutions) से आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत समर्थन
 7. आपदा प्रबंधन का व्यवसायीकरण (professionalisation)
 8. जोखिम खतरा और संवेदनशीलता विश्लेषण का आकलन (Assessment of Risk - Hazard and Vulnerability Analysis)
 9. जोखिम के बारे में जागरूकता (Awareness) पैदा करना

- 
10. आपदा प्रबंधन योजना को विकास योजनाओं (Development Plans) का हिस्सा बनाना |
 11. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स (EWS) सरकार के अलावा, सिविल सोसायटी और गैर सरकारी संगठन (NGOs) भाग ले सकते हैं |
 12. जोखिम-कटौती के लिए वित्तीय उपकरण (Financial Tools for Risk-Reduction) |

डॉ मिश्रा ने एसएफडीआरआर (SFDRR) और एशिया क्षेत्रीय योजना (Asia Regional Plan) के कार्यान्वयन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और समर्थन की पुष्टि की।

२१वीं सदी का भारत विश्वगुरु बनकर सम्पूर्ण विश्व का नेतृत्व करने वाला है। ऐसी परिस्थिति में हमें स्वाभाविक रूप से आपदा प्रबंधन में भी सशक्त रहना होगा। हमें भारत के ही नहीं बल्कि विश्व भर के आपदाओं से प्रभावी रूप से जान माल से आगे बढ़कर मानवता की रक्षा करना है।

धन्यवाद